



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514 ]  
No. 514 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2003/ज्येष्ठ 16, 1925  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2003/JYAISTHA 16, 1925

गृह मंत्रालय  
( एन. ई. डिवीजन )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2003

का.आ. 656(अ).—माननीय न्यायमूर्ति डा० एम०के० शर्मा की अध्यक्षता में गठित विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिकरण के समक्ष

अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल और हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ मेघालय को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 16.11.2002 की अधिसूचना सं० का०आ० 1203 (अ), भाग II, खण्ड (ii) के मामले में ।

आदेश

1. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय ने 16 नवम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं० का०आ० 1203 (अ) के द्वारा अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद 'ए एन वी सी' कहा गया है) और हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ मेघालय (जिसे इसमें इसके बाद 'एच एन एल सी' कहा गया है) को इस आधार पर विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया था कि उक्त संगठनों का घोषित उद्देश्य मेघालय में सुरक्षा बलों तथा नागरिकों पर हमला करके हिंसक उपायों के द्वारा मेघालय राज्य को भारत से पृथक् करना है । अपने अलगाववादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के रूप में विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने हेतु उनसे संपर्क बनाने के प्रयास करते रहे हैं ।

2. उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि (क) ए एन वी सी एवं एच एन एल सी के सशस्त्र गुटों और सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों तथा नागरिकों पर बार-बार और निरंतर हिंसात्मक कार्यकलाप एवं हमले किए जाते रहे हैं, (ख) ए एन वी सी और एच एन एल सी के संख्या बल में वृद्धि हुई है, (ग) ए एन वी सी और एच एन एल सी द्वारा निरंतर धन की वसूली, लूट-खसोट एवं अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति की जाती रही है, और (घ) ए एन वी सी और एच एन एल सी ने अभी भी आश्रय, प्रशिक्षण तथा छिपे तौर पर शस्त्र एवं गोला-बारुद प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं ।

3. चूंकि अधिनियम के अनुसार अधिकरण को यह न्याय-निर्णय करने के लिए कहा जाना था कि क्या उक्त संगमों अर्थात् ए एन वी सी और एच एन एल सी को विधि विरुद्ध-संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इसलिए भारत सरकार ने यह न्याय-निर्णय करने के लिए, कि क्या उक्त दोनों संगमों को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 14.12.2002 को इस अधिकरण के गठन संबंधी एक अधिसूचना जारी की थी। उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार पठित है :-

### "गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 2002

का०आ० 1318 (अ) : विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा यह न्याय-निर्णय करने के उद्देश्य से, कि क्या अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) और हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबेरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम०के० शर्मा की अध्यक्षता में "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

फा० सं० 9/6/2002-एन ई-1)

पी०के० जलाली, संयुक्त सचिव।

4. अधिनियम के अंतर्गत उक्त संगठनों को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने का कारण यह था कि उक्त दोनों संगठन अलगाववादी संगठन हैं। ए एन वी सी का गठन दिसम्बर, 1995 में किया गया था जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, नया 'अचिक लैण्ड' राज्य बनाने के लिए गारो पहाड़ियों को मुक्त कराना था। इस संगठन की गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र राज्य की पूर्वी गारो पहाड़ियां हैं। इस संगठन के नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (ईस्साक मुइवाह) (एन एस सी एन(आई/एम)) के साथ घनिष्ठ संबंध है। एच एन एल सी का प्रभाव पूर्वी और पश्चिमी खासी पहाड़ी जिलों में है। इन दोनों संगठनों के न केवल एन एस सी एन (आई/एम) के साथ बल्कि उल्फा, एन डी एफ बी जैसे पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। ए एन वी सी तथा एच एन एल सी को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अधिसूचना के द्वारा प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाने और इन पर लगे प्रतिबंध को आगे दो और वर्षों के लिए जारी रखने के समर्थन में भारत सरकार द्वारा उद्धृत कारणों में से कुछ कारण निम्नलिखित हैं -

- i. मेघालय के भारत से पृथक करने की नीति का निरंतर अनुपालन;
- ii. भारत की अखण्डता और सम्प्रभुता के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों में निरंतर संलिप्तता;

- iii. अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सशस्त्र कार्रवाई के जरिए हिंसा और आतंक का निरंतर सहारा लेना;
- iv. व्यवसायियों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों और जनता से अवैध कर-वसूली तथा उच्च स्तरीय लूट-खसोट;
- v. पूर्वोक्त के अन्य उग्रवादी संगठनों तथा पड़ोसी देशों से सम्पर्क एवं उनको सहायता देना; तथा
- vi. गुप्त रूप से या सुरक्षा बलों से छीनकर भारी संख्या में अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों और गोलाबारुद की प्राप्ति।

5. यह महसूस किया गया कि यदि उपरोक्त संगठनों को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित नहीं किया जाता है और अधिसूचना का विस्तार नहीं किया जाता है तो ये संगठन हालात का अनुचित फायदा उठाएंगे तथा पृथक्तावादी और विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अपने संवर्ग को सक्रिय करेंगे। यह भी महसूस किया गया कि इससे इन संगठनों के नेताओं को विदेशी शक्तियों से मिलकर खुलेआम ऐसे राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलाप करने का अवसर मिल जायेगा जो भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

6. यह संदर्भ प्राप्त होने पर ए एन वी सी और एच एन एल सी को, इस अधिनियम की धारा 4 की धारा 2 के अंतर्गत दिनांक 14 जनवरी, 2003 के आदेश के तहत नोटिस जारी करके पूछा गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर यह बताएं कि क्यों न उन्हें विधि-विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया जाए और क्यों न दिनांक 16 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना में की गयी घोषणा की पुष्टि करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया जाए। इन नोटिसों को भी उसी तरह प्रचारित करने के निदेश दिए गए जिस तरह केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना को दो राष्ट्रीय अखबारों तथा मेघालय में प्रकाशित एवं परिचालित दो स्थानीय अखबारों में छपवाकर तथा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित कराकर प्रचारित कराया था। इन नोटिसों को सभी सातों जिलों में प्रत्येक जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगाकर भी प्रचारित करने के निदेश दिये गये। यह भी निदेश दिया गया था कि किसी जवाब या याचिका की प्राप्ति के लिए ए एन वी सी तथा एच एन एल सी के लिए विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण हेतु "याचिका बाक्स" शब्द लिखा याचिका बाक्स जिलाधिकारी/उपायुक्त, शिलांग, मेघालय तथा उपायुक्त, तुरा, पश्चिमी गारोहिल्स, जिला शिलांग, मेघालय के कार्यालय के बाहर किसी जाने माने स्थान पर रखा जाए और संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त द्वारा याचिका बाक्स में प्राप्त/दर्ज जवाब/याचिकाओं, यदि कोई हों, को तत्काल अधिकरण को भेजा जाए ताकि अधिकरण उन पर समुचित आदेश जारी कर सके। केन्द्रीय सरकार की ओर से श्री रामफल, अवर सचिव, गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 फरवरी, 2003 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया कि यह नोटिस तीन स्थानीय अखबारों - "शिलांग टाइम्स" में दिनांक 17 जनवरी, 2003 को, 'मावफोर' में दिनांक 16 जनवरी, 2003 को तथा "सालान्तिनी जनेरा" में दिनांक 17 जनवरी, 2003 को प्रकाशित किया गया। इस हलफनामे के साथ अखबारों की कतरनों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। इस हलफनामे में यह भी बताया गया कि इस नोटिस की विषय वस्तु को आकाशवाणी और दूरदर्शन के शिलांग केन्द्रों से भी प्रसारित कराया गया था और मेघालय राज्य के सभी सातों जिलों में प्रत्येक उपायुक्त के कार्यालय के सूचनापट्ट पर लगाया गया था, और कि याचिका बाक्सों को पूर्वी खासी

हिल्स जिला, शिलांग, और पश्चिमी गारो हिल्स जिला, तूरा के उपायुक्तों के कार्यालयों में रखा गया था। तामील किये जाने संबंधी एक और हलफनामा श्री जी पी वाहलांग, प्रधान सचिव, मेघालय सरकार, राजनीति विभाग, मेघालय द्वारा भी दायर किया गया था। अधिकरण के निदेश पर पूर्वी खासी हिल्स जिला और पश्चिमी गारो हिल्स, तूरा, मेघालय के उपायुक्तों द्वारा भी हलफनामे दायर किए गए थे जिनमें शपथ पूर्वक यह कहा गया था कि अधिकरण के निदेशानुसार रखे गए किसी भी याचिका बाक्स में कोई अनापत्ति या अभ्यावेदन नहीं पाया गया। ए एन वी सी और एच एन एल सी सहित किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया गया था और ए एन वी सी और एच एन एल सी की ओर से कोई भी व्यक्ति निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं हुआ। इस स्थिति को देखते हुए ए एन वी सी और एच एन एल सी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वे एक-पक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत करें। तदनुसार, शिलांग में 15 मार्च, 2003 से एक-पक्षीय साक्ष्य की रिकार्डिंग करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में शिलांग में 15 मार्च, 2003 को अधिकरण ने सुनवाई की जिसमें केन्द्र सरकार और मेघालय सरकार के साक्ष्यों को रिकार्ड किया गया।

7. श्री रामफल, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार से पूछताछ की गई जिन्होंने अपने मामले के समर्थन में केन्द्र सरकार की ओर से दिनांक 14 फरवरी, 2003 को एक हलफनामा भी दायर किया था। अपने हलफनामे में उन्होंने बताया था कि ए एन वी सी और एच एन एल सी दोनों ही पृथक्तावादी संगठन हैं। ए एन वी सी का गठन दिसम्बर, 1995 में किया गया था जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, गारो हिल्स को स्वतंत्र करना, 'अचिक लैंड' नामक एक नया राज्य बनाना रहा है और कि इस संगठन की गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र राज्य का पूर्वी गारो हिल्स क्षेत्र है। हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त संगठन ने अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक मुइवाह) के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। उक्त हलफनामे के पैरा (3) में श्री रामफल ने एच एन एल सी नामक एक दूसरे संगठन के बारे में बताया और उक्त हलफनामे में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया गया कि उक्त संगठन भी पृथक्तावादी संगठन है और यह पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स जिलों में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि उक्त संगठन लूटमार करके और बलपूर्वक धन एकत्र करता है। यह धन वह अधिकांशतः गैर-आदिवासी व्यावसायियों से वसूल करता है। यह लूटे गए धन का प्रयोग अधिकांशतः हथियार प्राप्त करने और अपने संवर्गों को प्रशिक्षण दिलाने में करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संगठन ने पहले ही कुछ आधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं और यह कि इसके एन एस सी एन (आई/एम) के साथ तथा बांग्लादेश की एजेंसियों के माध्यम से इंटर सर्विसेज इटेलीजेंस के साथ भी गहरे संबंध हैं। यह भी बताया गया कि एन एस सी एन (आई/एम) द्वारा अपने कैपों को एच एन एल सी और ए एन वी सी के लिए आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग करने के अतिरिक्त वह उन्हें हथियार प्राप्त करने, संवर्गों को प्रशिक्षण दिलाने तथा मेघालय में वारदात करने में सहायता प्रदान करता है। अपने हलफनामे में उन्होंने ए एन वी सी और एच एन एल सी द्वारा वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान और मई, 2002 तक की गई हिंसा की प्रमुख घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की जो अनुलग्नक III पर दी गयी है। उक्त हलफनामे के साथ संक्षिप्त विवरण भी दिया गया जिसमें इन दोनों संगठनों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया गया। अपने साक्ष्य के दौरान श्री रामफल ने अपने हलफनामे में किए गए उक्त सभी बयानों को दोहराया। उन्होंने उक्त संक्षिप्त विवरण को भी सिद्ध किया है जिसमें दोनों संगठनों की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाया गया है तथा जिसे एक्स सी

डब्ल्यू-1 और सी डब्ल्यू-2 के रूप में सिद्ध किया गया है। उक्त दो प्रदर्शों में दोनों संगठनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उनके पदाधिकारियों के नाम तथा हिंसा की प्रोफाइल विस्तार से दी गयी है और पूर्वोक्त के अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संबंधों का ब्यौरा भी दिया गया है। उक्त प्रदर्शों में दोनों संगठनों के विदेशी संबंध भी दिखाए गए हैं। श्री रामफल ने सी डब्ल्यू-3 भी सिद्ध किया है जिसमें इन दोनों संगठनों द्वारा वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान और मई, 2002 तक की गई हिंसा की प्रमुख घटनाओं की सूची दी गई है।

8. मेघालय राज्य ने भी मेघालय सरकार के राजनैतिक विभाग के प्रधान सचिव श्री जी०पी० वाहल्लोंग के माध्यम से अपना हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामे में उन्होंने ए एन वी सी तथा एच एन एल सी की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने सभी प्रासंगिक संलग्नक प्रस्तुत किए। अपने हलफनामे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस जैसे ऐतिहासिक दिवसों पर बंद का आह्वान करके ए एन वी सी ने अपनी राष्ट्रविरोधी तथा अलगाववादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की है। उक्त के समर्थन में उन्होंने ए एन वी सी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति भी संलग्न की जो अनुलग्नक 'क-10' पर है। उन्होंने हलफनामे में यह भी उल्लेख किया कि ए एन वी सी अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम जनता विशेषतः व्यवसायियों को डराने-धमकाने, जबरन धन वसूलने तथा लूटपाट में लिप्त है। उक्त हलफनामे में ए एन वी सी के खिलाफ दायर आपराधिक गतिविधियों/मामलों की एक सूची अनुलग्नक क-11 पर दी गई है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि ए एन वी सी के एन एस सी एन (आई/एम), असम के उल्फा तथा एन डी एफ बी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं, जिनकी पुष्टि ए एन वी सी के शिविरों पर छापा मारने से बरामद हुए दस्तावेजों से होती है, जिन्हें हलफनामे के साथ अनुलग्नक क-12 के रूप में संलग्न प्रेस क्लिपिंग, आसूचना रिपोर्ट द्वारा सिद्ध किया गया। उक्त अधिकारी ने वर्ष 2002 के दौरान ए एन वी सी द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों तथा अन्य सुरक्षा बलों के कार्मिकों की एक सूची भी अनुलग्नक क-13 के रूप में संलग्न की। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2002 के दौरान ए एन वी सी के कम से कम 52 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त सदस्यों से बरामद शस्त्रों एवं गोलाबारूदों का ब्यौरा भी अनुलग्नक क-14 के रूप में शपथपत्र के साथ संलग्न किया। उक्त अधिकारी के अनुसार, एच एन एल सी ने भारत संघ से राज्य को पृथक करने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप में दर्शाया है। एच एन एल सी ने एक 17 सूत्रीय कार्यक्रम प्रकाशित किया है जिसमें एच एन एल सी का उक्त दृष्टिकोण तथा अनुलग्नक क-15 में दर्शाए गए अनुसार उनका अलगाववादी दृष्टिकोण भी प्रदर्शित होता है। एच एन एल सी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी है जो उनकी अलगाववादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। उक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम में यह उल्लिखित है कि संगठन स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहा है और अपनी मातृभूमि एवं लोगों को भारतीय उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा उग्र-राष्ट्रीयता से मुक्त करना चाहता है। एच एन एल सी के उक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा 'वायस ऑफ एच एन एल सी' की प्रतियां अनुलग्नक क-16 पर संग्रहित रूप में रिकार्ड में रखी गई हैं। उक्त संगठन ने गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर भी बंद तथा असहयोग के लिए विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियां जारी की थी। उक्त तर्क के समर्थन में प्रेस क्लिपिंग अनुलग्नक क-17 पर संलग्न हैं। उक्त संगठन के एन एस सी एन (आई/एम), असम के उल्फा तथा मणिपुर के के वार्ड के एल जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं। उक्त तर्क के समर्थन में प्रेस क्लिपिंग/आसूचना रिपोर्ट हलफनामे के साथ अनुलग्नक क-21 के रूप में संलग्न है। ए एन वी सी तथा एच एन एल सी दोनों की विधि-विरुद्ध गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक क-22 तथा क-23 पर

संलग्न है। उक्त अधिकारी ने एच एन एल सी द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की एक सूची तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये एच एन एल सी के कार्यकर्ताओं के नाम तथा बरामद किए गए शस्त्रों एवं गोलाबारूदों की एक सूची भी प्रस्तुत की। ऐसे शस्त्रों एवं गोलाबारूदों की एक सूची अनुलग्नक क-20 के रूप में रिकार्ड में भी रखी गई है। श्री जी०पी० वाहलॉग ने उक्त हलफनामा प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने आप को एक गवाह के रूप में भी प्रस्तुत किया और उन्होंने उक्त शपथपत्र की पुष्टि की जो प्रदर्श ए के रूप में इंगित है। उन्होंने उक्त दोनों संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की भी पुष्टि की जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-1 / 1 तथा एस डब्ल्यू 1/2 के रूप में सिद्ध हो चुकी है। उपरोक्त घोषणा को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया तथा अधिसूचना आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के साथ-साथ विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी जो पूछताछ के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्ध होता है। कार्यवाही के दौरान गवाह ने शपथपत्र में कहे अपने कथन को दोहराया तथा विभिन्न दस्तावेजों के सिद्ध किया जो प्रदर्श क-3 से प्रदर्श क-23 तक के रूप में हैं। मेघालय सरकार में पश्चिमी खासी पहाड़ी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री बी०आर० राणा (एस डब्ल्यू-2), पूर्वी खासी जिला, शिलांग की पुलिस अधीक्षक सुश्री आई० नोंगरेज (एस डब्ल्यू-3), श्री डब्ल्यू० खेलेप, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी खासी हिल्स जिला (एस डब्ल्यू-4), श्री ओ० पासी, पुलिस अधीक्षक, जैन्तिया हिल्स, (एस डब्ल्यू-5), श्री एस०एस० यादव, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी गारो हिल्स (एस डब्ल्यू-6), श्री एफ डी संगमा, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी गारो हिल्स, विलियम नगर (एस०डब्ल्यू०-7), श्री एस० जगन्नाथन, उपायुक्त, पश्चिमी गारो हिल्स जिला, तुरा (एस०डब्ल्यू०-8), श्री एस नोंगसीज, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नोंगस्टोइन (एस०डब्ल्यू०-9) से भी पूछताछ की गई। उन्होंने श्री जी पी वाहलॉग द्वारा अपने साक्ष्य में दिए गए बयान को दोहराया और उसकी पुष्टि की। उक्त गवाहों ने एक्स एस० डब्ल्यू० -2/1, एक्स एस० डब्ल्यू०-3/1 और एक्स एस डब्ल्यू-6/1 को भी साबित किया है। एक्स एस डब्ल्यू 1/22 में ए एन वी सी और एच एन एल सी के प्रशिक्षित संवर्गों और गतिविधियों की सूची, 25.11.92 से 30.6.2002 तक इन संगठनों के गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की सूची और 20.6.2000 से 11.6.2002 तक ए एन वी सी के मारे गए कार्यकर्ताओं की सूची दी गई है। उक्त गवाहों ने उपरोक्त सूची का उल्लेख और समर्थन किया जिसमें ए एन वी सी और एच एन एल सी द्वारा की गई वारदातों की प्रकृति का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदातें इन सूचियों में उल्लिखित जिलों में की गई थीं। उक्त गवाहों को संबंधित जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक होने के नाते, इन वारदातों की जानकारी है।

9. उन्होंने यह बयान दिया कि दोनों उक्त संगठन व्यवसायियों से धन ऐंठना, सुरक्षा बलों के कार्मिकों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर हमले करना और उनकी हत्या करना जैसे कार्यों में लिप्त हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि दोनों संगठनों के सदस्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए तथा हथियार और गोलाबारूद खरीदने के लिए, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों और पुलिस पर हमले करने के लिए किया जा रहा है, धन इकट्ठा करने हेतु सिविलियन लोगों को भयभीत करते और लूटते रहे हैं। उन्होंने यह बयान दिया कि दोनों संगठन मेघालय राज्य के अनेक भागों में विद्रोही और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार विशेष तौर पर बंगलादेश में अपने शिविर स्थापित किए हैं तथा उनके आई०एस०आई० जैसी विदेशी एजेंसियों और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध हैं। उन्होंने दोनों उग्रवादी गुटों के सदस्यों के विरुद्ध दायर विभिन्न

आपराधिक मामलों को सिद्ध किया और ऐसे लंबित मामलों की सूचियां उन्होंने अपने साक्ष्य के दौरान सिद्ध की हैं। लगभग सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि यदि उनकी गतिविधियों को तुरंत रोका और नियंत्रित नहीं किया गया तो इस बात की संभावना है कि ये संगठन पुनर्गठित हो जाएंगे और फिर हथियारों से लैस हो जाएंगे जिससे वे मेघालय राज्य को भारत से अलग करने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियों को तेज करेंगे।

10. मैंने भारत संघ और मेघालय सरकार की ओर से शपथपूर्वक दिए गए बयानों और दायर किये गये शपथ पत्रों को पढ़ा है। उक्त साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया और उसे चुनौती नहीं दी गई। उक्त बयानों और शपथपत्रों से ए एन वी सी और एच एन एल सी दोनों गुटों की राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी प्रवृत्तियों का पता चलता है। उक्त दोनों गुट गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे ऐतिहासिक दिनों पर बंद का आह्वान करते रहे हैं। ये गुट हथियार खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से सिविलियन लोगों, विशेष रूप से व्यवसायियों को भयभीत करने, उनसे धन ऐंठने और लूटपाट करने के कार्यों में लिप्त हैं। उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की सूचियां भी दायर की गई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि वे पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों के कर्मियों पर हमले करते रहे हैं। यह भी सिद्ध होता है कि उनके एन एस सी एन (आई/एम) एवं असम के उल्फा जैसे प्रतिबंधित संगठनों और आई एस आई, जो कि बंगलादेश से अपनी गतिविधियां चला रही है, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। उक्त तथ्य ए एन वी सी और एच एन एल सी के शिविरों पर छापों के दौरान जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेजों से सिद्ध हुआ है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे ऐतिहासिक दिनों पर बंद और असहयोग का आह्वान करने संबंधी दोनों गुटों द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतियां भी रिकार्ड में रख ली गई हैं।

11. रिकार्ड में रखे गए उक्त दस्तावेजों से और गवाहों के बयानों से यह सिद्ध होता है कि दोनों संगठनों का लक्ष्य अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना और भारत के संविधान और संप्रभु सीमाओं से बाहर एक पृथक राष्ट्र बनाना है। इन संगठनों के कार्य क्षेत्रों में मुख्यतः पूर्वी गारो हिल्स तथा पश्चिमी खासी हिल्स शामिल हैं। इन संगठनों के पास अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र हैं जिन्हें गैर-कानूनी तरीकों से प्राप्त किया गया है। ये संगठन भारत से अलगाव की नीति का भी समर्थन कर रहे हैं। ये उन कार्यकलापों में भी लिप्त हैं जो भारत की प्रभुसत्ता और एकता के लिए अहितकर हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल करके हिंसा और आतंक फैलाते हैं। साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि ये लूट-खसोट करते हैं। दिए गए साक्ष्यों, वारदातों तथा दर्ज किए गए एवं लंबित मामलों की सूची से यह पता चलता है कि ये व्यापारियों सहित नागरिकों से लूट-खसोट कर रहे हैं और उनसे गैर-कानूनी ढंग से धन इकट्ठा कर रहे हैं और कि इनके पूर्वोक्त के अन्य अलगाववादी विद्रोही संगठनों से संबंध हैं और उन्हें इनका समर्थन प्राप्त है। वे पड़ोसी बंगलादेश में अपने शिविर बनाते जा रहे हैं तथा गुप्त माध्यमों से और यहां तक कि बंगलादेश से भी बड़ी संख्या में अत्याधुनिक शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त कर रहे हैं। ये संगठन नागरिकों, सशस्त्र कर्मियों की हत्या कर देते हैं और लूटमार, लूट-खसोट एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और इस तरह अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं।

12. इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(च) तथा 2(छ) के उपबंधों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें 'विधिविरुद्ध कार्यकलाप' तथा 'विधिविरुद्ध संगम' को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

2. "परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX

(च) किसी व्यक्ति अथवा संगम के संबंध में विधिविरुद्ध कार्यकलाप का अर्थ ऐसे व्यक्ति अथवा संगम द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य (किसी कार्य के निष्पादन द्वारा अथवा लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा, अथवा संकेतों द्वारा अथवा स्पष्ट प्रदर्शन द्वारा अथवा अन्यथा) है-

(i) जिसका आशय, किसी भी आधार पर, भारतीय भूभाग के किसी भाग का पृथकीकरण अथवा भारतीय भू भाग के किसी भाग का संघ से अलगाव करना या उसका समर्थन करना हो अथवा जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को इस प्रकार के अलगाव या पृथकीकरण के लिए प्रेरित करता हो या ऐसा करने संबंधी किसी दावे का समर्थन करता हो;

(ii) जो भारत की संप्रभुसत्ता तथा भू-भागीय अखंडता को अस्वीकार करता हो, उसका विरोध करता हो, उसे विरूपित करता हो, या विरूपित करने का इरादा करता हो;

(छ) "विधिविरुद्ध संगम" का अर्थ ऐसा संगम है -

(i) जिसका उद्देश्य कोई विधिविरुद्ध कार्यकलाप करना हो, अथवा जो व्यक्तियों को ऐसा विधिविरुद्ध कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता हो अथवा समर्थन देता हो, अथवा जिसके सदस्य ऐसे कार्यकलाप करते हों; अथवा

(ii) जिसका उद्देश्य ऐसा कार्यकलाप हो जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153 क या 153 ख के अंतर्गत दंडनीय हो अथवा जो व्यक्तियों को ऐसा कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करे अथवा समर्थन दे, अथवा जिसके सदस्य ऐसा कोई कार्यकलाप करें;

बशर्ते कि उपखंड (ii) में उल्लिखित बातों में से कोई भी बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगी। "

13. अधिनियम के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन भी इस संबंध में काफी संगत है जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

### "उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता एवं प्रादेशिकता समिति की एकमत सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार करने के अनुसरण में, संविधान (16वां संशोधन) अधिनियम, 1963 को



अधिनियमित किया गया था जिसमें संसद को भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के हित में, कानून द्वारा निम्नलिखित पर यथोचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया था :

- (i) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
- (ii) शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने का अधिकार; तथा
- (iii) संगम अथवा संघ बनाने का अधिकार ।

2. इस विधेयक का उद्देश्य भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यकलापों से निपटने के लिए शक्तियां प्राप्त करना है।"

14. पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त साक्ष्य को ऊपर उल्लिखित कानूनी प्रावधानों के आलोक में पढ़े जाने पर यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि दोनों ही संगठन नामतः ए एन वी सी तथा एच एन एल सी विध्वंसकारी/ अलगाववादी, हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और आम लोगों, सेना तथा सशस्त्र कर्मिकों को मारने, प्रच्छन्न माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों एवं गोलाबारूद के प्रापण हेतु मेघालय में आम जनता एवं व्यापारियों से धन लूटने जैसे कार्यों में संलिप्त हैं । दोनों ही संगठनों का लक्ष्य एवं उद्देश्य भारत से संबंध विच्छेद करके एक अलग राज्य की स्थापना करना है । उनके पूर्वोत्तर के अन्य अलगाववादी विद्रोही संगठनों से संबंध हैं तथा उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है । अतः रिकार्ड से प्राप्त सामग्री से यह सिद्ध होता है कि अगर इन संगठनों को अपनी गतिविधियां चलाने की अनुमति दी जाएगी तो ये और अधिक विद्रोही एवं गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे । उनकी संपूर्ण कार्यवाहियों एवं गतिविधियों से भारत की संप्रभुता एवं भू-भागीय अखंडता विखंडित होगी तथा यदि इन पर रोक या प्रतिबंध न लगाया गया तो न केवल इनकी गैर-कानूनी गतिविधियों में वृद्धि होगी अपितु राज्य में भारत से अलगाव का वातावरण भी बन सकता है । अतः इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए स्पष्ट खतरा है जो स्पष्टतः अधिनियम के भाग 2 (च) में परिभाषित विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों में आती हैं ।

15. पूर्वोक्त कारणों से, मैं संतुष्ट हूँ कि ए एन वी सी तथा एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण थे । तदनुसार, यह अधिकरण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (I) के तहत दिनांक 16.11.02 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पुष्टि करता है ।

**न्यायमूर्ति डॉ० एम०के० शर्मा**  
**विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण**

दिनांक 5 मई, 2003

[सं. 9/6/2002-एन.ई.-I]  
राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****(N. E. Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2003

**S.O. 656(E).—BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)  
TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE JUSTICE DR. M. K. SHARMA.**

In the matter of : Notification No. SO.1203(E) dated 16.11.2002, Government of India, Ministry of Home Affairs, Part II, Section (ii), declaring Achik National Volunteer Council and the Hynniewtrep National Liberation Council of Meghalaya, as unlawful associations.

**ORDER**

1. By notification No. S.O.1203(E) published in the Gazette of India (Extraordinary) on November 16, 2002, the Central Government, Ministry of Home Affairs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as 'the Act'), declared the Achik National Volunteer Council (hereinafter referred to as 'the ANVC') and the Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter referred to as 'the HNLC') of Meghalaya to be unlawful associations on the ground that the said organisations have as their professed aim and objective the secession of State of Meghalaya from India through violent means by attacking the security forces and the civilian population in Meghalaya. They have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. It is stated in the notification that (a) there have been repeated, continuing and ongoing acts of violence and attacks by armed groups and members of the ANVC and the HNLC on the Security Forces and the civilian population; (b) there has been an increase in the strength of the ANVC and the HNLC; (c) there has been continued collection of funds and extortions and acquisition of sophisticated weapons by the

ANVC and the HNLC; and (d) the camps in some neighbouring countries continue to be maintained by the ANVC and the HNLC for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

3. Since in terms of the Act, a reference has to be made to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the aforesaid associations, namely, ANVC and HNLC as unlawful associations, the Government of India issued a notification dated 14.12.2002 under sub section (1) of Section 5 of the Act constituting this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause of declaring the said two organisations as unlawful associations. The said notification reads as under:

**“MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14<sup>th</sup> December, 2002

S.O.1318(E).- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice M.K.Sharma, Judge of the Delhi High Court for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Achik National Volunteer Council (ANVC) and Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) as unlawful associations.

[F.No.9/6/2002-NE-I]  
P.K.JALAJI, Jt.Secy.”

4. The object of declaring the aforesaid organisations as unlawful organisations under the Act was that the said two organisations are secessionist outfits. ANVC was formed in December 1995 with the aim of, among other things, liberation of Garo Hills to achieve a new State of ‘Achik Land’. The activities of the

outfit are mainly confined to the East Garo Hills of the State. The outfit has been maintaining close connection with National Socialist Council of Nagaland (Isak Muivah) (NSCN(IM)). HNLC has its influence in East and West Khasi Hills Districts. Both these outfits have maintained close links with not only NSCN(IM) but also with other North East militant outfits like the ULFA, NDFB. Some of the reasons which have been cited by the Government of India in support of continuation of the ban and extension of notification declaring the ANVC and HNLC as unlawful organisations under the Unlawful Activities (Prevention) Act for a further period of two years are as follows:

- i. continued espousal of the policy of secession of Meghalaya from India;
- ii. continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- iii. continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective;
- iv. high levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even government employees;
- v. links and support to other North-East militant groups and with neighbouring countries; and
- vi. procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

5. It was felt that unless the aforesaid organisations are declared unlawful organisations and the notification is extended, these organisations may take undue advantage of the situation and mobilise their cadres for escalating secessionist and subversive, terrorist and violent activities. It was also felt that it may provide an opportunity to the leadership of these organisations to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concerns.

6. On receipt of the reference, vide order dated January 14, 2003 notices were issued under section (2) of section 4 of the Act to the ANVC and the HNLC calling upon them to show cause within thirty days from the date of service of the notice why they should not be declared unlawful and an order should not be made confirming the declaration made in the Notification dated November 16, 2002. Notices were directed to be served in the same manner as the notification had been served by the Central Government by serving through two daily National newspapers and two local newspapers circulated and published in Meghalaya as well as by broadcasting on radio and television. Notices were also directed to be served by pasting the same on the notice boards of the offices of each of the District Magistrates of all the seven districts. It was also directed that a petition box with words "Petition Box" for Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for the ANVC and the HNLC inscribed on it, for receipt of any reply/petition be installed at a conspicuous place outside the office of the District Magistrate/Deputy Commissioner, Shillong, Meghalaya and the Deputy Commissioner, Tura, West Garo Hills, District Shillong, Meghalaya, and such petitions/replies received/filed in the petition box, if any, shall be immediately transmitted to the Tribunal by the respective Deputy Commissioner/District Magistrates to enable the Tribunal to pass appropriate orders thereon. The Central Government filed an affidavit of Shri Ram Phal, Under Secretary, Ministry of Home Affairs, dated February 15, 2003 stating that notice was published in three local newspapers, namely, 'Shillong Times' dated January 17, 2003; 'Mawphor' dated January 16, 2003; and 'Salantini Janera' dated January 17, 2003. Copies of the newspaper clippings were also filed along with the affidavit. It is also stated in the affidavit that the contents of the notice were broadcast through Shillong Station of the All India Radio; that the notice was also telecast by the Doordarshan

Kendra, Shillong; that the notice was pasted on the notice boards in the offices of all the seven Deputy Commissioners in the State of Meghalaya; and that the petition boxes were installed in the offices of the Deputy Commissioners of East Khasi Hills District, Shillong, and West Garo Hills District, Tura. Another affidavit of service was also filed by Shri G.P. Wahlang, Principal Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Meghalaya. On the direction of the Tribunal, affidavits were filed by the Deputy Commissioners, East Khasi Hills District, and West Garo Hills, Tura, Meghalaya, stating on oath that no objection or representation was found in any of the petition boxes which were installed pursuant to the orders of the Tribunal. No opposition was filed by any of the parties including the ANVC and the HNLC, and none appeared on behalf of the ANVC and the HNLC on the date fixed. In view of the same, the ANVC and the HNLC were proceeded ex parte and the Central Government and the State Government were directed to lead ex parte evidence. Accordingly, the matter was fixed for recording ex parte evidence at Shillong on March 15, 2003 onwards. Pursuant to the said order, sitting of the Tribunal was held in Shillong on 15<sup>th</sup> March, 2003, when evidence adduced by the Central Government and the Govt. of Meghalaya was recorded.

7. The Central Government, in support of its case, was examined through Shri Ram Phal, Under Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, who also filed his affidavit dated February 14, 2003. He has stated in his affidavit that both ANVC and HNLC are secessionist outfits. ANVC was formed in December 1995 with the aim of, among other things, liberation of Garo Hills to achieve a new State of 'Achik land' and that the activities of the outfit are mainly confined to the East Garo Hills of the State. It has also been contended in the affidavit that the said outfit has been maintaining close links with National Socialist Council of Nagaland (Isak Muivah)

{NSCN(I/M)} in its violent activities. In paragraph (3) of the said affidavit Mr. Ram Phal has stated about the other organisation, namely, HNLC contending, inter alia, that the said organisation is also a secessionist outfit and has influence in East and West Khasi Hill Districts. He has stated that the said outfit has been able to raise large sums of money regularly through looting and extortion, mostly from non-tribal businessmen and that most of the money from such extortion was being utilised for procuring weapons and training of its cadres. He also stated that the outfit has already procured some sophisticated weapons and has close connections with NSCN(I/M) and also Inter-Services Intelligence through Bangladesh agencies. It is also stated that NSCN(I/M) has been helping the HNLC and ANVC in procuring of arms, training of their cadres and in their operations in Meghalaya, besides providing their camps as hideouts. He in his affidavit has annexed a detailed report of major instances of violence committed by ANVC and HNLC during the years 1999, 2000, 2001 and upto May 2002, which is annexed as annexure-III. Along with the said affidavit a resume giving details of the various activities being carried out by the two organisations have been set out. During the course of his deposition, Shri Ram Phal has reiterated all the aforesaid statements made in his affidavit. He has also proved the aforesaid resume indicating the various activities of the two organisations which is proved as Ex.CW-1 and CW-2. The said two exhibits set out at length the aims and objectives of both the organisations, names of their office bearers and the violence profile and also giving details of their links with other North East Extremists Groups. The said exhibits also indicate the foreign links of both the outfits. CW-3 is also proved by Mr. Ram Phal which gives a list of major incidents of violence committed by the two outfits during the years 1999, 2000, 2001 and upto 31<sup>st</sup> May 2002.

8. The State of Meghalaya also filed their affidavit through Shri

G.P.Wahlang, who is the Principal Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department. In the said affidavit he has dealt with the various activities of the ANVC and HNLC. He has submitted all relevant annexures. He has categorically stated in his affidavit that ANVC has clearly reflected their anti national and secessionist tendencies by giving calls for bandhs on historic days like Republic Day and on Independence Day. In support of the said contention he has annexed the press releases given by ANVC, which is annexure 'A-10'. He has also stated in the affidavit that ANVC has been employing and engaging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population particularly businessmen for the purpose of achieving the objectives of their organisation. In the said affidavit a list of criminal activities/cases registered against the ANVC is annexed as Annexure-A-11. He has also reiterated that ANVC has close links with banned organisations like NSCN(I/M), ULFA of Assam and NDFB of Assam, which is established from the documents seized from the raided ANVC camps, which are proved through the press clippings, intelligence reports annexed with the affidavit as Annexure A-12. The said officer also annexed a list of police personnel and other security forces killed by the ANVC during the year 2002, which is annexed as Annexure A-13. He has also stated that as many as 52 members of ANVC cadres have been arrested during the year 2002 and arms and ammunition seized from the said members is also annexed with the affidavit as Annexure -A-14. According to the said officer, HNLC have clearly indicated their objective of secession of the State from the Union of India. HNLC have published a 17 point programme, which reflect the aforesaid stand of HNLC and also indicate their secessionist stand as indicated from annexure A-15. HNLC also have a 20 point programme, which also reflects their secessionist trend. One of the said 20 point programme stated that the outfit demands and voice for freedom and to



unchain their mother land and people from the Indian colonialism, imperialism and chauvinism. The said 20 point programme of HNLC and copies of the voice of HNLC have been placed on record collectively as annexure A-16. The said outfit had also issued various press releases calling for bandh and non-cooperation even on Republic Day and Independence Day celebrations. Press Clippings in support of the said contention are annexed as annexure A-17. The said outfit has very close links with the banned NSCN(I/M), ULFA of Assam and KYKL of Manipur. In support of the said contention press clippings/intelligence reports have been annexed with the affidavit as annexure A-21. Detailed unlawful activities of both ANVC and HNLC have also been annexed as annexures A-22 and A-23. The said officer has also submitted a list of police personnel, security forces killed by HNLC and the names of the HNLC cadres who have been arrested by the police and also a list of arms and ammunition that have been recovered. A list of such arms and ammunition has also been placed on record as annexure A-20. Mr.G.P.Wahlang after tendering the said affidavit also examined himself as a witness and he has proved the said affidavit, which is marked as Ex.A. He has also proved the notification issued by the Central Government declaring the said two outfits as unlawful, which is proved as Ex.SW-1/1 and SW-1/2. Wide publicity was given about the aforesaid declarations and notifications published in various newspapers as also through All India Radio and Doordarshan Kendra, which are proved by documents placed during the course of his examination. The witness examined himself in the proceeding and he has reiterated his statements made in his affidavit and also proved several documents, which are proved as Ex.A-3 to Ex.A-23. The Government of Meghalaya also examined Sh.B.R.Rana, Superintendent of Police, West Khasi Hills District, (SW-2), Ms.I.Nongrang, Superintendent of Police, East Khasi District, Shillong (SW-3).

1567 GI/03-3

Sh.W.Khylllep, Additional District Magistrate as also In-Charge District Magistrate, East Khasi Hills District (SW-4), Sh.O.Pasi, Superintendent of Police, Jaintia Hills (SW-5), Sh.S.S.Yadav, Superintendent of Police, West Garo Hills (SW-6), Sh.F.D.Sangama, Superintendent of Police, East Garo Hills. William Nagar (SW-7), Sh.S.Jagannathan, Deputy Commissioner, West Garo Hills District, Tura (SW-8), Sh.S.Nongsiej, Additional District Magistrate, West Khasi Hills District, Nongstoin (SW-9). They have reiterated and corroborated the statement made by Mr.G.P. Wahlang in his evidence. The said witnesses have also proved the Ex.SW-2/1, Ex.SW-3/1 and Ex.SW-6/1. Ex. SW-1/22 contains list of the names of the trained cadres of ANVC AND HNLC and also their activities and the arrests made from 25.11.92 upto 30.6.2002 and also a list of ANVC activists killed from 20.6.2000 upto 11-6-2002. The aforesaid witnesses also mentioned and supported the aforesaid list containing the nature of incidents committed by ANVC and HNLC. They stated that such incidents had taken place in the districts mentioned therein. The said witnesses being Deputy Commissioners and the Superintendents of Police of the concerned districts are aware of the said incidents.

9. They have stated that both the outfits have been carrying on their activities like extortion of money from businessmen, attacking and killing security forces, the government employees and also ordinary citizen. They have also deposed that members of the two outfits in furtherance of their objectives have been intimidating and looting civilian population for collection of funds for their organisational activities and also for purchase of arms and ammunition, which are being used for attacking security forces and the police. It was stated by them that both the organisations were engaged in subversive and secessionist activities in many parts of the State of Meghalaya and have established their camps across the International

Border, particularly Bangladesh and has links with foreign agencies like ISI and with other banned organisations. They have proved the various criminal cases registered against the members of the two militant outfits and the lists of such pending cases have been proved by them during their deposition. Almost all the witnesses have categorically stated that unless their activities are immediately curbed and controlled, there is a possibility of their regrouping and rearming themselves which would accelerate their activities with a view to secession of the State of Meghalaya from India.

10. I have perused the aforesaid statements made on oath as also the affidavits filed on behalf of the Union of India and the Government of Meghalaya. The said evidence go unrebutted and unchallenged. The said statements and affidavits reveal the anti national and secessionist tendencies of both ANVC and HNLC. Both the said outfits have been giving calls for bandhs on historic days like Republic Day and Independence Day. They are also engaged in the acts of intimidation, extortion and looting of civilian population particularly businessmen for collection of funds to buy arms. Lists of criminal cases pending against them has also been filed which prove and establish that they have been attacking police personnel and other security forces. It is also proved and established that both the outfits have close links with banned organisations like NSCN(I/M), ULFA of Assam and ISI, who is functioning from Bangladesh. The said fact has been proved by the various documents seized from the raids on ANVC and HNLC camps. Copies of the press release issued by both the outfits calling for bandhs and non-cooperation on historic days like Republic Day, Independence Day celebrations have been placed on record.

11. It is proved from the aforesaid documents placed on record and also from the statements of the witnesses that objective of both the outfits is to establish an

5576/103-4

independent identity and a separate country outside the Constitution and sovereign boundaries of India. The area of operation of these organisations mainly include Eastern Garo Hills and East and West Khasi Hills. These organisations possess sophisticated fire arms procured through illegal means. They are also advocating to follow the policy of secession from India. They are also indulging in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India. They also indulge in violence and terrorism through arms actions with a view to achieve their objective. The evidence also proves that they are indulging in extortion. Evidence led and the list of incidents and the cases filed and pending indicate that they are also indulging in extortion and illegal collection of money from civilians including businessmen, traders and that they have links and support of other north eastern secessionist insurgent groups. They are continuing to maintain their camps in neighbouring Bangladesh and are procuring large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels and even from Bangladesh. The organisations are indulging in killing of civilians, armed personnel and are resorting to looting, extortion and other criminal acts and are thus creating a climate of lawlessness.

12. In this regard a reference can be made to the provisions of Section 2(f) and 2(g) of the Act, which defines "unlawful activity" and "unlawful association" as under:

2. Definitions. -- In this Act, unless the context otherwise requires -

XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX

(f) 'unlawful activity', in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise)

(i) which is intended, or supports any claim to bring about, on

any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

(g) "unlawful association" means any association -

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity:

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir."

13. The Statement of Objects and Reasons of the Act has also very relevance in that regard which states as follows :-

#### "STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS"

Pursuant to the acceptance by Government of a unanimous recommendation of the Committee on National Integration and Regionalism appointed by the national Integration Council, the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, was enacted empowering Parliament to impose, by law, reasonable restrictions in the interests of the sovereignty and integrity of India, on the -

- (i) freedom of speech and expression.
- (ii) right to assemble peaceably and without arms; and
- (iii) right to form associations or unions

2. The object of this Bill is to make powers available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India."

14. The aforesaid evidence led by the parties when read in the light of the aforesaid provisions of law clearly prove and establish that both the outfits namely, ANVC and HNLC, are indulging in subversive, secessionist and violent activities and are resorting to acts of killing civilians, army and police personnel, extortion of funds for public and traders in Meghalaya for procuring sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels. The aims and objectives of both the organisations are to secede from India and to form a separate State. They have links and support of other North East secessionist insurgent groups. It is clearly, therefore, established from the material on record that if these organisations are allowed to continue with their activities, they would further indulge in insurgent and unlawful activities. The entire course of their action and their activities would lead to disruption of the sovereignty and territorial integrity of India and if they are not checked or banned, not only that the unlawful activities would increase but also an atmosphere may be created in the State for secession from India. These activities are thus a clear threat to the sovereignty and integrity of the country, which clearly amount to unlawful activities as defined under Section 2(f) of the Act.

15. For the foregoing reasons, I am satisfied that there was sufficient cause for declaring the ANVC and HNLC as unlawful associations. This Tribunal, accordingly, confirm the declaration made by the Central Government vide notification dated 16.11.2002 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

**JUSTICE DR. M.K. SHARMA**  
**UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL**

May 5th, 2003

[No. 9/6/2002-N.E.-I]  
RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.